

محترمہ محسنہ فدوانی (چھتیس گڑھ) : لگ بھگ 100 پولیس والوں کی چھتیس گڑھ میں موت ہو چکی ہے۔ میرا سبھاؤ بوم منسٹری کو یہ ہے کہ آندھرا پردیش، آڑیسہ، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ وغیرہ جتنے اسٹیٹس ہیں، ان سب کا ایک کمبائنڈ آپریشن ہونا چاہیے نکلوا دے خلاف، کیوں کہ یہ بہت بڑی لعنت ہو رہی ہے۔

श्री उपसभापति : श्रीमती मोहसिना किदवई, सुश्री मेबल रिबेलो associated. श्री प्रकाश जावडेकर।

श्री श्रीगोपाल व्यास : सर, मेरा नाम बोला गया था...(व्यवधान)...

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : सर, श्री श्रीगोपाल व्यास जी का क्या हुआ?

श्री उपसभापति : इन्होंने associate किया है।

Lack of security coordination in the aviation sector

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, मेरा समय अभी शुरू हो रहा है, यह जरा बता दें।

उपसभापति महोदय, देश की सुरक्षा की जो बात हमारे एक साथी ने उठाई, उसी का एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने सदन के माध्यम से उठा रहा हूँ कि देश की सुरक्षा के बारे में जब आतंकवादी हमले होते हैं तो मंत्री ऐसा बताते हैं कि हम सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से चौकस हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, इससे अभी परिचय हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई है। कुछ पैसेजर्स द्वारा Indigo flight में जो hijack का alert दिया गया था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सों ने कैसे react किया, इसकी जो रिपोर्ट आई है, वह चौंकाने वाली है। पौने पांच बजे 3 पैसेजर्स ने झगड़ा किया और कहा कि हम hijack करेंगे। 5 बजे पॉयलट ने hijack alarm की बात की और नीचे ग्राउंड पर बता दिया। साढ़े पांच बजे emergency landing हुई, लेकिन NSG, local police, Airport Authority की security agencies में तालमेल का अभाव होने के कारण वे आपस में झगड़ने लगे, यहां तक कि उनमें कोई coordination नहीं था। NSG commandos को तैयार होने में 30 मिनट लगे, जो एयरपोर्ट पर खड़े थे। इतना ही नहीं वहां एयरप्लेन के आस-पास लाइट लगाएं या नहीं, इस पर भी एक राय नहीं हुई। उसी बीच कंट्रोल टावर की hotline भी फेल हो गई और officials unsecured mobile से बात कर रहे थे और उनमें तालमेल का अभाव था। यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी के बारे में हम कितने बेफिक्र हैं और क्या चित्र है। यह सब 26/11 के बाद हुआ है। मंत्री जी कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन लगता है कि उनका administration पर और security apparatus पर कोई control नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सिक्योरिटी पर भी राजनीति करते रहेंगे? मुंबई में 26/11 के बारे में राम प्रधान कमेटी नियुक्त हुई थी, उनकी रिपोर्ट आई है कि इसमें क्या-क्या lapses थे, लेकिन राजनीति के कारण वह घोषित ही नहीं हो रही है, उसे लोगों के सामने लाया ही नहीं जा रहा है। अगर इस तरह से हम लापरवाही बरतेंगे, तो मुझे

* Not recorded

लगता है कि सिक्योरिटी के मामले पर हमें जो ध्यान देना चाहिए, वह हम नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि security lapses को दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी, इसका action plan बता दें और मेरी दूसरी मांग यह है कि राम प्रधान कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसे भी सदन में पेश किया जाए।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, गुजरात में बहुत अत्याचार हो रहा है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, आपका नोटिस नहीं आया है, आप नोटिस दीजिए, ज़ीरो ऑवर में नोटिस के बगैर नहीं लिया जाता...(व्यवधान).... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव शुक्ल : उपसभापति जी, *

श्री उपसभापति : आप बैठिए, आप पहले नोटिस दीजिए, तब लेंगे। Now, we take up the Special Mentions. Those Members who want to lay their Special Mentions, they can lay it. ...*(Interruptions)*...

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : उपसभापति जी, मैंने एक नोटिस दिया था...(व्यवधान)...

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा) : सर, किसानों की बात कोई नहीं सुनेगा क्या? पंजाब में बारिश नहीं हुई है, हरियाणा में बारिश नहीं हुई है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : तरलोचन सिंह जी, आप बैठिए...(व्यवधान)...

सरदार तरलोचन सिंह : सर, पंजाब में बारिश नहीं हुई है, हरियाणा में बारिश नहीं हुई है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : उसके बारे में आ गया है, पहले बात हो गई है...(व्यवधान).... एक subject पहले आ गया है, दोबारा उसे फिर नहीं लेते, यह आ गया है...(व्यवधान).... वोरा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री मोती लाल वोरा : मैंने भी इसी के संबंध में सूचना दी थी कि छत्तीसगढ़ के...(व्यवधान).... मैंने आपको दिया था...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह लेट आया था, जो लेट आते हैं, उसे नहीं लेते हैं, there is a procedure for that. ...*(Interruptions)*...

सरदार तरलोचन सिंह : मैंने तो तीन दिन पहले टाइम पर दिया था...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका वह सब्जेक्ट डिस्कस हो चुका है, प्लीज़ आप लोग बैठिए...(व्यवधान)...

Now, those Members who want to lay their Special Mentions, they can lay it; otherwise, if they want to speak, they can do it only after 5 o'clock. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: We will speak at 5 o'clock. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : Lay करने वाले lay कर सकते हैं। Shall I call the names? Dr. Pilania, do you want to lay it?

* Not recorded

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, I am forced to lay it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not, forced to lay it. You can do it after 5 o' clock. ...*(Interruptions)*...

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Sir, on principle, Special Mentions should be read. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; what we have decided is this. If there is time, still there is five minutes' time. ...*(Interruptions)*...

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Do you think, Sir, it is fair to say, 'come at five, then you will be able to read it?' ...*(Interruptions)*... Come at six, then you will be able to read it. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं बाद में ...*(Interruption)*... Only five minutes are there. ...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS

Concern over alarming scenario of skewed sex-ratio

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, it is a matter of grave concern that declining trend in sex ratio has reached alarming proportions, particularly steep decline in the child sex ratio for the age group of 0-6 years. In 2001, in 927 girls per thousand boys against 945, recorded in 1991 Census, a decline in 18 points. The overall sex ratio in India was 972 in 1901, 927 in 1991 and 933 in 2001, which has further declined in 2006. This highly skewed sex ratio (number of females per thousand males), is primarily because of female foeticide. The findings of a study published in Lancet, states that '10 million female foetuses have been aborted in India over the last two decades'. Thus based on conservative assumptions, pre-natal sex determination practices account for about 0.5 million missing female births yearly. It is highly disturbing that the Census 2001 reveals that the child sex ratio is comparatively lower in the affluent regions, *i.e.*, Punjab 798, Haryana 819, Chandigarh - 845, Delhi - 868, Gujarat - 883 and Himachal Pradesh - 896.

In order to check female foeticide, the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, was brought into operation from 1st January, 1996 and to make it more comprehensive, the amended Act and Rules came into force with effect from 14.2.2003. But, this has not proved effective. Hence, I would strongly urge the Central and State Governments to take stringent measures, on war-footing, to 'SAVE THE GIRL CHILD' from 'MURDER in the WOMB'.